[Shri H. M. Patel]

(ii) The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 1976, published in Notification No. S.O. 761(E) in Gazette of India dated the 1st December, 1976.

[*Placed in Library. See* No LT-16/77].

(2) A copy of the Emergency Risks (Goods) Insurance (Fifth Amendment) Scheme, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 792(E) in Gazette of India dated the 14th December, 1976, under sub-section (6) of section 5 of the Emergency Risks (Goods) Insurance Act, 1971. [*Placed in Library. See No. LT-17/77*].

(3) A copy of the Emergency Risks (Undertakings) Insurance (Sixth Amendment) Scheme, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 793 (E) in Gazette of India dated the 14th December, 1976, under sub-section (7) of section 3 of the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Act, 1971. [*Placed in Library. See* No. LT-17/77].

(4) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Industrial Finance Corporation of India for the year ended the 30th June, 1976 along with the statement showing the Assets and Liabilities and Profit and Loss Account of the Corporation, under sub-section (3) of section 35 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948. [*Placed in Library. See* No. LT-18/77]

(5) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Industrial Development Bank of India together with the Audited Accounts of the General Fund and the Development Assistance Fund for the year ended the 30th June, 1976, under sub-section (5) of section 18 and sub-section (5) of section 23 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964.

[*Placed in Library. See* No. I - 19/77].

11.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ARRESTS MADE IN CONNECTION WITH ALLEGED TRANSMISSION OF IMPORTANT AND CLASSIFIED INFORMATION TO INTELLIGENCE AGENCIES OF CERTAIN FOREIGN COUNTRIES

श्री श्याम सुन्दर दास (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस बारे मे एक वक्तव्य दें :

> "कुछ विदेशों के दूतावासों के माध्यम से उन की गुप्तचर एजेंसियों को आर्थिक और सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी दिये जाने के बारे में की गई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां के समाचार।"

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH): Sir, the espionage activities referred to in the Calling Attention Notice are under investigation. For reasons of security, however, it would not be in public interest to disclose the facts at this stage.

श्री श्याम सुन्दर दास : अध्यक्ष महोदय, आप को निश्चित रूप से स्मरण होगा कि आज से करीब साल, डेढ़ साल पहले डीसूजा, जो प्रैस सूचना विभाग के डायरेक्टर रह चुके थे, इसी आरोप में गिरफ्तार किये गए थे और

न्यायालय ने उन्हें 12 वर्ष की रिगोरस इम-प्रिजनमेंट की सजा दी थी । 26 मार्च के फ़िनांशल एक्सप्रेस में दिबिगेस्ट एवर एसपायनेज केस" के शीर्षक से इसी केस का जिक्र किया गया है कि आजादी के बाद यह पहला मौका है कि इंटलिजेंस ब्यूरो ने यह जान लेने के बाद कि इस देश मे श्रीमती इन्दिरागांधी की हुकूमत नहीं रह गई है, यह हिम्मत की कि एक दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन मे योजना आयोग के तीन वरिष्ठ पदा-धिकारी शामिल हैं । उन व्यक्तियों मे पूर्वी योरुप के एक दूतावास में काम करने वाली पूर्वी योरूप की एक महिला भी है, जो एक भारतीय व्यापारी की पत्नी है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ पेपर मे आया है वही आप बोल रहे हैं ।

श्री श्याम सुन्दर दास : मैं आपके माध्यम से अति महत्वपूर्ण बात की जानकारी दे रहा हूं जिस ओर प्रस का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन संयोगवश अभी तक सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया । आप को स्मरण होगा कि विली ब्रांट जो पश्चिमी जमनी के चांसलर रह चुके हैं, उनके निजी सचिव भी इसी तरह पूर्वी जर्मनी की सरकार को कुछ सूचना देने के आरोप मे पकड़े गए तो विली ब्रांट ने चांसलर पद से इस्तीफा दिया । भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री यशवत राव बलवंत राव चव्हाण जो प्रतिपक्ष के माननीय नेता हैं, के निजी सचिव भी इस आरोप में गिरफ्तार किए गए । ये सारे के सारे लोग सी आई ए जो अमेरिका की एजेंसी है और के जी बी जो सोवि-यत रूस की एजेंसी है इन दोनों महाशक्तियों की गुप्तचर एजेंसियों को अति महत्वपूर्ण सामरिक और आर्थिक सूचनाएं प्रास्पेक्टिव प्लानिंग आयरन ऐंड स्टील, एलेक्ट्रिसिटी, केमिकल ऐंड फर्टिलाइज़र आदि के संबंध मे प्रस्तुत करते रहे हैं । मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय नेता से भी अपेक्षा करता हूं कि वे कम से कम एक परसनल एक्स-प्लेनेशन दें क्योंकि विली ब्रांट ने फोन पर इस्तीफा दिया था । अगर यह आरोप सत्य सिद्ध होता है कि उनके सचिव का संबंध इस केस से है और यह उनकी जानकारी में था तो शायद इस सदन को अधिकार है कि वह उन्हें इस सदन की सदस्यता से वंचितक सके ।

दूसरी बात मैं दुख के साथ कहता हूं कि गृह मंत्री आड़ लेते हैं कि लोक हित मे इसे प्रकट करना उचित नहीं होगा । संसार का सर्वोच्च जनतंत्र अमेरिका है । वहां आज निक्सन के बाद जिमी कार्टर का शासन आया है । जिमी कार्टर ने घोषणा की है कि कैबिनेट की मीटिंग में भी वे प्रस का एलाऊ करेंगे । यह अमेरिकन डेमोक्रेसी की स्पिरिट है ।

MR. SPEAKER: You are making a speech.

SHRI SHYAM SUNDER DAS: I am not making a speech. I am only making a submission through you to the hon. Minister of Home Affairs not to resume the old practice of the Indira Gandhi Government of taking Shelter behind 'public interest'.

अब हिन्दुस्तान में प्रपंच और झूठ की राजनीति चल नहीं सकती । इस सदन को विश्वास में लेना होगा और मैं मांग करता हूं कि एक परसनल एक्सप्लेनेशन लीडर आफ दी अपो-जीशन दें ।

दूसरी मांग मेरी यह है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बने जिस में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लोग रहे और यह जो संसार की महाशक्तियां हिन्दुस्तान को बराबर कमजोर बनाए रखना चाहती हैं, एक तरफ इंडो सोवियत ट्रीटी भी है और दूसरी तरफ अति महत्व की हमारी सूचनाएं खरीदी जा रहीं हैं अमेरिका की ओर से और सोवियत रूस की ओर से, इस चीज को देखा जाए । इस सदन मे कुछ ऐसे भी सदस्य है जिनको सी आई ए नजर

[श्री श्याम सुन्दर दास]

आता है लेकिन उन को के जी बी नजर नहीं आता है। आज शंकर दयाल शर्मा जी यहां नहीं है जिन्हें आन्दोलन के पीछे सी० आई० ए० नजर आता था। ०००० (व्यवधान)

मेरी तीसरी मांग आप के माध्यम से यह है कि सरकार रूस और अमेरिका को नरमी के साथ, पोलाइटली यह वार्निंग दे कि अब नई जनता सरकार इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा रिश्ता रूस और अमेरिका से बराबरी का होगा। हम दरिद्र हैं धन से लेकिन चरित्र से नहीं।

चौधरी चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र के पास जो सूचना है अगर मुझे देने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं उस का फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो आप ने कहा कि कैबिनेट में पिटिशन वगैरह बुलाई जाए तो मेरा कहना आप को यह है कि पहले इस हाउस में बुलाना शुरू कीजिए।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): This is a very big CIA case. But I would like to make it clear that, if foreign intelligence agencies are involved, they should also be firmly dealt with. In our country's internal affairs, we would not tolerate such an espionage activity from any quarter. It is an outcome of the erstwhile Prime Minister Shrimati Indira Gandhi's and her Government's attitude. I quote from a clipping of 1972:

> "A demand by Opposition leaders that the Government shou'd set up a Parliamentary Committee to inquire into CIA activities in depth or publish a white paper on the subject was today rejected by the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi."

This is the position. Thanks to the press, they have revealed it, and it is good that these things are revealed, so that people come to know and Government also could be brought to the position where they can take steps.

This was a question put by me on the 13th December, 1972:

> "whether American Columnist Jack Anderson had revealed in one of its articles the links between ITT and the CIA in some cloak and dagger exploits allegedly carried out in Latin America; and if so, the Government's reaction thereto."

The reply is:

> "(d) and (e). Government are aware of the recent disclosures in the American Press of the links between CIA and the ITT and due note has been taken thereof."

ITT has a big ramification in this country. They were in collaboration with the erstwhile Government.

Here is a very big case and which is the firm involved? I would not say anything involving the security of the country: I assure you, Sir, and the people in power. The firm is LURGI India Ltd., it is one of the largest importing firms of civil engineering equipment and their office is in a building owned by Birlas in Delhi. The Managing Director is of German origin but a Swiss citizen. I would like to know from the Home Minister whether it is a fact that he is wanted in Germany for war crimes and that he is a declared fugitive. Is it also a fact that he is friendly and pally with our ex-Prime Minister's son, Sanjay Gandhi? Is it also a fact that he had some connection with Piper plane business in this country?

Some twelve or thirteen persons were arrested in connection with the case. One is Shri R. P. Varshnoi, Director, Metals, Planning Commission, formerly of Defence Ministry, a sensitive Ministry as far as the security of the country is concerned. There was a raid in his house and a number of microfilms of documents, apart from cash, were found. It is a

very serious matter. Foreigners visited him quite frequently and he was very often out for lunch etc. in luxury hotels. Who paid for this? This has to be found out by Intelligence.

Another person arrested was Shri Mahavir Prasad, former Additional Private Secretary of the erstwhile Foreign Minister, Shri Chavan. Is it also a fact that because of this action, some pressure was put on him before the elections? I am not blaming or involving Shri Chavan at all, but I would like to know, if it is a fact that somebody in his party tried to put pressure using this as a handle.

Shri Varshnoi was teaching in ITT, Kharagpur, which received huge aid from USA. Another accused is Shri K. K. Sarin, Director of Perspective Planning. What are thes seizure when the raid was carried out in his house? The other arrested persons are Shri Pannikar, Senior Research Officer in the Health Unit, Shri Eknath Choudhury, Senior Officer (Metals), STC, and some officers of MMTC and Steel and Mines Ministry.

A Canadian-USA firm, Metchew, had been given contract for Kudremukh along with Bechtal (of the pipeline scandal) which was revealed by the Takhru Commission. The operation is controlled by a CIA man with an assumed name, Tedler, if I am right. Let the Home Minister confirm or deny this. Besides other things, they wanted to know the details of special metals used for MIG and other important defence equipment. I would like to tell the House how they operate. The scrapping of the factory that was producing aircraft in a particular country was sold to an outsider. Those were melted and used for making coat hangers. These coat hangers were used in an aircraft. They bribed the sweeper; the coat hangers was thrown in the waste paper basket. They picked it up, analysed the metal to see whether that metal could cause vibration and whether that metal could stand the metal fatigue that any aircraft would develop. That is the way they work.

I would also like to know if some officers of the United States Wing of the External Affairs Ministry are also involved. Let this be confirmed or denied. Is it also a fact that Shri Jagat Mehta, Secretary-General of the External Affairs Ministry, tried to stop publication of this? Did he make such a request in the name of national interest? I would also like to know the names and details of the U.S. diplomats declared person non-grata in recent months. Some time ago, under some pressure, the erstwhile Government had ordered a probe into the conduct of the foreigners working for foreign firms in India. I would like to know the outcome from the Home Minister and the External Affairs Minister. May I know who are the liaison men who work for the Government of India undertakings and big firms and who got special photo passes from the Home Ministry? I would like to know how many passes have been issued and how many withdrawn during the last three months.

I would like to come to one or two things more....

MR. SPEAKER: You want to exhaust all your papers. You are expected to ask only one question. Now, please conclude.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The **New York Times**, in its issue dated 10th May, 1975 has clearly indicated that the multi-national corporations in India, viz., the Union Carbide, Hindustan Levers, Liptons, Firestone, etc. are on the pay-roll of CIA and they do get paid in dollars and that money goes straight into their pockets. Let the Home Minister inquire and find out.

I would like to know about the Boeing deal—the commission taken by certain big persons and certain parties. What were the conditions and the consideration?

[Shri Jyotirmoy Bosu]

Burmah-Shells also have admitted that they have paid commission to Indian officials, etc.

Bechtel, that notorious firm, has been given contracts in Kudremuch within the country.

Sir, there are big former officials on the pay of foreign firms. These are all very dangerous things.

MR. SPEAKER: Now, please allow the Minister to say something.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I will take only one more minute.

The previous Government has entered into a contract with the American firm, International Dynamics. For what? For providing electronic surveillance of the Indo-China border...

MR. SPEAKER: How does it arise?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The involvement of foreign espionage at every level of our life—at the official level, at the political level, at the commercial level and at every level...

MR. SPEAKER: It is only calling attention to a particular subject How is it connected? Please now conclude.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have put this specific question. I would like the hon. Minister or any other Minister who is now in charge of these things to tell us whether it is a fact or not and what are the specific details and information and what specific preventive measures they are going to take.

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि इस वक्त सदन के सामने जो प्रश्न है, वह बड़ा गम्भीर और व्यापक है, लेकिन जब तक उसके बारे में तहकीकात पूरी नहीं हो जाएगी – माननीय सदस्य जो अभी बोल चुके है, वे भी इस बात से सहमत होंगें —कि यह जनहित में नहीं है कि वे बातें खोल दी जाएं वरना इसका इनवेस्टीगेशन सहीं नहीं हो सकेगा। जैसे ही इन्वैस्टीगेशन कम्पलीट होगा, मैं सदन के सामने सारे कान्क्लूजन्ज और रिजल्ट्स रख दूंगा।

दूसरी बात — माननीय सदस्य ने और भी बहुत सी शिकायतों का जिक्र किया है, मैं आप के जरिए उन से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे सारी सूचनाएं मेरे पास भेज दें और मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट उन पर जो भी कार्यवाही करेगी उसके बाद उनकी कोई शिकायत नहीं रहेगी।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय हम दुनियां के सभी देशों से अच्छे सम्बन्ध चाहते हैं, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि हमारे देश की स्वतन्त्रता में और अन्दरुनी मामलों में कोई देश हस्ताक्षेप न करे। इस लिए यह जो एस्पाएनेज का केस है, यह भारत के इतिहास में सब से बड़े केसेज में से एक है। इसके अन्दर करीब एक दर्जन आफीशिवल्ज और मिनिस्टर के पी० ए० और कुछ मल्टीनेशनल कम्पनीज भी इन्वाल्वड है। आश्चर्य यह है कि आर० पी० वार्ष्णय जो डायरैक्टर (मैटल्ज) प्लानिंग कमीशन में हैं, वे सी० आई० ए० और के० जी० बी० दोनों के एजेन्ट है, यह एक अजीब मिश्रण है कि वे दोनों से पैसा ले रहे थे और दोनों को इन्फर्मेशन पास कर रहे थे। आप इस बात को भी जानते हैं कि ये बड़ी बड़ी ताकतें जैसे यू० एस० ए० एक साल में 6 बिलियन डालर्स एस्पाएनेज पर खर्च करता है। इसी तरह से के० जी० बी० भी करोड़ों रुपए खर्च करता है। हमारे देश की सिक्योरिटी के बारे में एक किताब निकली है — सी० आई० ए० – दि कल्ट आफ इन्टेलिजेन्स—इस

किताब में लिखा है कि नार्थ इण्डिया में सी० आई० ए० एक्टिविटीज और के० जी० बी० एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। इस लिए मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं—

1. क्या यह सही है कि दो अमरीकन्ज को भारत सरकार ने हिन्दुस्तान से बाहर निकाल दिया? इसके बारे में अमरीकन एम्बेसी ने कोई कमैन्ट नहीं किया है, यह बात अखबार में निकली है?

2. क्या इसमें कुछ मल्टीनेशनल कम्पनीज, जिनमें "लुगी इण्डिया" तो शामिल है ही, इसके अलावा भी कुछ अन्य कम्पनीज इन्वाल्व्ड है?

3. मैं विदेश मंत्री महोदय से यह सवाल पूछना चाहता हूं — क्या वे इस चीज पर विचार करेंगें कि इस सवाल को इन्टरनेशनल लेवल पर उठाया जाए और दूसरे देशों से सम्पर्क किया जाए कि इस तरह की एक्टिविटीज एक देश दूसरे देश में न करे। इस तरह का कोई कोड दुनिया के सामने बनना चाहिए।

4. आखरी सवाल — हमारे देश में इस तरह की एक्टिवीटीज बन्द हों —इस के लिए सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है?

क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की जो इटेंलिजेंस थी, वह अपोजीशन के ऊपर लगी हुई थी। अब देश की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस लगाई जाए, इस प्रकार की व्यवस्था क्या सरकार कर रही है?

चौधरी चरण सिंह: , अध्यक्ष महोदय, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं उसी को दोहराते हुए एक वाक्य और एड करना चाहता हूं और वह यह है कि जब माननीय मित्र मुझसे बात कर लेगें और उस पर जो गर्वनमेंट कार्यवाही करेगी, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी और उनको यह मानना पड़ेगा कि गर्वनमेंट जितनी कार्यवाही कर सकती थी, उतनी उसने की।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, I want to raise the point about release of detenus. I want to darw the attention of the House to this important matter. I have given notice.

MR. SPEAKER: We pass on to the next item of the Agenda.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have no information whether you have disallowed it. This is a very important matter, regarding release of political prisoners.

MR. SPEAKER: You cannot get up and say such things whenever you like.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampure): In the other House it has been mentioned and the Minister replied.

MR. SPEAKER: I am on my legs. You cannot just get up and shout like this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I wrote to you, Sir.

MR. SPEAKER: Everyday I get hundreds of letters or notices. It does not mean that you can get up every time and say these things. If other Members also who send such notices get up and start speaking about it, there will be no end to it. No I am sorry. This is not at all proper. Please don't do it. The House is for all the 542 Members, not for one Member alone. Please don't do it.